



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1420]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2009/भाद्र 17, 1931

No. 1420]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2009/BHADRA 17, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2009

सं. 06/2009-2014

विषय : शैड सींगों की शेविंग्स का निर्यात—ढील संबंधी ।

का.आ. 2281(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 50/(आर ई-2006)/2004-2009 दिनांक 9 मार्च, 2006 के पैरा (क) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

“(क) निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 5 की क्रम सं. 39 और 40 के मद्दे कॉलम 5 में निर्धारित शर्त में 30-9-2009 तक की अवधि तक चीतल और सांभर के शैड सींगों की शेविंग और चीतल और सांभर के शैड सींगों से विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी ।”

2. उपरोक्त विस्तार के संबंध में विनिर्देश और शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(क) भावी निर्यातक विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में मांगी गई मात्रा और विधिक प्रापण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित मुख्य वन्य जीव रक्षक के पास निर्यात के यूनिट मूल्य के लिए अपने आवेदन जमा करवाएंगे;

(ख) मुख्य वन्य जीव रक्षक विधिक प्रापण प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले निर्यात किए जाने वाली प्रस्तावित सामग्री के वास्तविक स्टॉक की जाँच करवाएगा;

(ग) इसके पश्चात्, राज्य सरकार मुख्य वन्य जीव रक्षक द्वारा जारी विधिक प्रापण प्रमाण-पत्र सहित संबंधित मामलों को अनुमति के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजेगी;

(घ) इसके पश्चात् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, मामला दर मामला आधार पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास निर्यात की सिफारिश करेगा;

(ङ) संबंधित दस्तावेजों सहित प्रत्येक निर्यात खेप मौजूदा मानदण्डों और प्रक्रियाओं के अनुसार पोत लदान पूर्व निरीक्षण और जाँच के अधीन होगी;

(च) एक बारगी छूट 30-9-2009 तक होगी;

(छ) यह उल्लेख किया जाता है कि यदि आवेदक के पास पुराना स्टॉक बच भी गया है, तो भी निर्यात परमिट देने के लिए विधिक प्रापण प्रमाण-पत्र जारी करना होगा;

(ज) निर्यात के लिए अनुमति शैड सींगों के केवल उसी सामान के लिए दी जाएगी जिसका पहले बढ़ाई गई अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया जा सका, बाद में प्राप्त किए गए किसी स्टॉक के लिए यह अनुमति नहीं दी जाएगी ।

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 01/91/180/975/एम 05/निर्यात सैल (पार्ट)]

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2009

**No. 06/2009-2014****Subject : Export of shavings of Shed Antlers—  
relaxation regarding.**

**S.O. 2281(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 read with Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes, the following amendments in the Para (a) of Notification No. 50(RE-2006)/2004-2009 dated 9th March, 2006, as under :—

“(a) The condition stipulated in Column 5 against Sl. Nos. 39 and 40 of Chapter 5 of Schedule 2 of the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items shall be relaxed for a period up to 30-9-2009 to allow export of Shavings of Shed Antlers of Chital and Sambhar and Manufactured Articles of Shavings of Shed Antlers of Chital and Sambhar.”

2. The specifications and conditions with respect to the above extension are as under :—

(a) The prospective exporters will submit their applications in the prescribed form within 30 days from the date of issue of Notification by the DGFT, containing therein the quantity applied for and the unit price of export to the concerned Chief Wildlife Warden for obtaining Legal Procurement Certificate;

- (b) The Chief Wildlife Wardens shall undertake the Physical Stock verification of the material proposed to be exported before issuing Legal Procurement Certificates;
- (c) Thereafter, the State Government may refer the respective cases along with the Legal Procurement Certificate issued by the Chief Wildlife Warden to Ministry of Environment and Forest, Government of India for grant of permission;
- (d) Ministry of Environment and Forest, will thereafter, recommend the export, on case to case basis to the DGFT;
- (e) Each export consignment along with the related documents will be subject to pre-shipment inspection and verification as per the existing norms and practices;
- (f) The one time exemption will be up to 30-9-2009;
- (g) It is mentioned that even if the old stock are held with the applicant, Legal Procurement Certificate has to be issued for grant of export permit;
- (h) The permission for export shall be for only those left out material of shed antlers, which could not be exported during the extension given earlier and not for any stock, procured thereafter.

3. This issues in Public interest.

[F. No. 01/91/180/975/AM 05/Export Cell (Part)]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade  
& ex-officio Addl. Secy.